

3
11.08.17

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

न्याय अनुभाग - 2.

देहरादून : दिनांक: 4 जुलाई, 2017

विषय: राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 19-दो(2)/XXXVI(2)/15-01-दो(2)/15-टी0सी0 दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके तहत मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के प्रयोजनार्थ आकस्मिकता निधि से विभिन्न मदों में राज्य आकस्मिकता निधि से रू0 2.08 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम रू0 2,08,00,000/- (रूपये दो करोड़ आठ लाख मात्र) की धनराशि की प्रतिपूर्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट से किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देश के कम में धनराशि की प्रतिपूर्ति ऑन-लाईन कर दी गई है, जिनकी अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या: S1707040018 दिनांक 04 जुलाई, 2017 संलग्न है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 17(2)/XXXVI(2)/2017-01-दो(2)/15-टी0सी0-तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 3- वित्त अनुभाग-5/एन0आई0सी0/गाई फाईल।

आज्ञा से,
(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव।